

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान

आई.ए.एस.

संख्या 170/2020

1. विनोद पुत्र सत्यनारायण, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 51, मोतीसिंह की ढाणी, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. बजरंग लाल पुत्र कुरड़ाराम जाति माली, निवासी वार्ड नं0 51, मोतीसिंह की ढाणी, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू।

—अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए भूमि धारक तहसीलदार झुंझुनू।
2. श्री अशोक सैनी पुत्र श्री नन्दलाल सैनी, जलाति माली, निवासी अशोक नगर, बगड, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. श्री अशोक सैनी पुत्र नागरमल, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 51, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू।

—रेस्पोंडेन्टस

—
अपील निरस्त करवाने नामान्तरकरण संख्या 4157 स्वीकृत दिनांक 12.02.2020 कस्बा झुंझुनू
—

1. श्री अशोक सैनी, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से
2. श्री सुरेश कुमार सैनी, एडवोकेट— रेस्पोंडेन्ट सं0 3 की ओर से
3. श्री अशोक सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोंडेन्ट सं0 1 की ओर से.

आदेश

दिनांक 30.03.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के आदेश दिनांक 12.02.2020 नामान्तरकरण संख्या 4157 के कस्बा झुंझुनू के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की ओर से अपील इस प्रकार पेश है कि राज्य सरकार द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ते को समस्या निराकरण के लिए उक्त अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु रास्तों का प्रस्ताव जरिये तहसीलदार को

जिला कलक्टर झुंझुनू

उन्होंने राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का परिपत्र दिनांक 16.08.2016 को जारी किया गया था।
 नं० प.3(2) राजस्व 6/2003/पार्ट जयपुर के उक्त क्रमांक के अनुसार झुंझुनू कस्बा में
 रास्ता जो खसरा नम्बर 2181, 2186, 2185 व 2199 में प्रचलित रास्ता जाता था
 पटवारी व तहसीलदार ने जांच कर उक्त राज्य सरकार के आदेश के अनुसार उक्त खसरा
 रास्ता प्रचलित था उसको राजस्व रिकार्ड में अनुशंषा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू में
 दर्ज थी उक्त अनुशंषा के अनुसार उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 09.12.2016 को
 नम्बरान प्रचलित रास्ते को कटान करने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप संभागीय
 आयुक्त ने एक अपील संख्या 323/19 शीर्षक ख्यालीराम बनाम राजस्थान सरकार के नाम से
 प्रस्तुत की थी जिसमें संभागीय आयुक्त ने दिनांक 11.12.2019 को अपील स्वीकार कर
 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि
 दोनों पक्षों को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए
 विधि सम्मत निर्णय पारित करे। संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.12.2019 के अनुसार
 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनू में विचाराधीन है परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार
 झुंझुनू ने दिनांक 21.02.2020 को नामान्तरकरण संख्या 3583 में खसरा नम्बर 2181, 2186,
 पटवारी नम्बर देते हुए जिसमें खसरा नम्बर 4467/2187, 4468/2186, 4469/2185
 दर्ज कर रकबा क्रमशः 0.06, 0.05, 0.03 की भूमि को पुनः खातेदारी में दर्ज कर दी
 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनू में विचाराधीन है। इसी दौरान तहसीलदार ने
 संभागीय आयुक्त का हवाला देते हुए दिनांक 12.02.2020 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के
 दिनांक 09.12.2016 के अनुसार रास्ते की इन्द्राजात को पुनः बदला है इस नामान्तरकरण में किस
 प्रार्थना पत्र दिया जाकर तहसीलदार से नामान्तरकरण दर्ज करने का नाम दर्ज नहीं किया
 जाकर तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया है अथवा तहसीलदार अपने स्वविवेक से
 रास्ता हटा कर खातेदारी भूमि दर्ज की है उसका रीजन नहीं बताया है जबकि अभी
 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है तब तक पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 3583
 को तहसीलदार द्वारा बदलने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि अभी रास्ते का उपयोग उपभोग
 खातेदारों ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनू में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश
 है उनके खेतों में जाने वाला रास्ता जो कायम था उसको कुछ व्यक्तियों ने मौके पर बंद
 कर दिया है। इसलिए संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 11.12.2019 प्रकरण को पुनः
 निर्णय पर रास्ते का निरीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे परन्तु कुछ असामाजिक तत्व इस
 रास्ते को बंद करने पर आमादा है। अभी दिनांक 26.08.2020 को इस रास्ते पर पडने वाला
 दिनांक कुमर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को निवेदन किया कि कुछ व्यक्ति पटवारी से
 नामान्तरकरण में इस रास्ते की भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाकर रास्ते की भूमि पर
 चालू किया है तो खातेदारों ने इसका विरोध करते हुए उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र
 फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को रूकवाया है। अभी रास्ता चालू है ऐसी
 तहसीलदार झुंझुनू द्वारा दिनांक 12.02.2020 को नया नामान्तरकरण संख्या 4157 दर्ज कर
 भूमि को हटा कर उसमें बरानी भूमि खातेदारी की दर्शाकर विधि के नियमों के विरुद्ध कार्य
 कर रहा तो तहसीलदार व हल्का पटवारी उपखण्ड अधिकारी को उक्त प्रचलित रास्ते की
 जांच करे जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 09.12.2016 को उक्त प्रचलित रास्ते
 को हटाने का आदेश दिया था अब इसके विपरीत संभागीय आयुक्त के आदेश से रास्ते की भूमि को
 हटा दिया गया जैसा कि संभागीय आयुक्त के निर्णय को देखते हुए स्पष्ट है कि संभागीय
 आयुक्त को रिमांड किया है। सम्पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं किया है व दोनों पक्षों को साक्ष्य
 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनू को पुनः भेजा है ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से

20
 जिला कलेक्टर जयपुर

लेकर प्रकरण में व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रास्ते की भूमि को पुनः दर्ज कर विधि विरुद्ध व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है। इसलिए न्यायिक संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 को दौरान प्रकरण विचाराधीन तस्दीक किया है उसको रद्द किया जावे। अपीलान्त को उक्त नामान्तरकरण संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 की पूर्व में दर्ज नहीं थी लेकिन दिनांक 26.08.2020 को व इससे पूर्व दिनांक 20.08.2020 को प्रचलित रास्ते को रोक कर निर्माण कार्य की कोशिश करने की जानकारी हुई व उसके बाद अपीलान्त को दस्तावेज व नकल निकला कर उक्त नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी हुई। अतः अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 4157 की जगह नया नामान्तरकरा संख्या 4157 खातेदारी की भूमि में दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे व दौरान अपील मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपीलान्त की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा दिनांक 09.12.2016 को खसरा नम्बरान प्रचलित रास्ते को कटान करने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप संभागीय जयपुर में एक अपील संख्या 323/19 शीर्षक ख्यालीराम बनाम राजस्थान सरकार के नाम से अपील प्रस्तुत की थी जिसमें संभागीय आयुक्त ने दिनांक 11.12.2019 को अपील स्वीकार कर अपील को पुनः उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि उभय पक्षों को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए उक्त विधि सम्मत निर्णय पारित करे। संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 11.12.2019 के अनुसार अपीलान्त उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं में विचाराधीन है परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 21.02.2020 को नामान्तरकरण संख्या 3583 में खसरा नम्बर 2181, 2186, 2187 को पुनः बट्टा नम्बर देते हुए जिसमें खसरा नम्बर 4467/2187, 4468/2186, 4469/2185 में खसरा दर्ज कर रकबा क्रमशः 0.06, 0.05, 0.03 की भूमि को पुनः खातेदारी में दर्ज कर दी है। अपीलान्त मामला उपखण्ड अधिकारी न्यायालय झुंझुनूं में विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3583 की जगह नया नामान्तरकरा संख्या 4157 खातेदारी की भूमि में दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 बाद नियमानुसार भरा गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। अतः अपील अपीलान्त को निरस्त किया जावे।

बहस के दौरान विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंड सं० 2 व 3 ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्त मातहत द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील संख्या 323/2019 में निर्णय दिनांक 11.12.2019 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 4157 दिनांक 12.02.2020 को रद्द किया है। उक्त माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.12.2019 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के आदेश दिनांक 09.12.2016 को निरस्त किया गया है तथा प्रकरण सुनवाई हेतु अपीलान्त किया गया है। जब आदेश दिनांक 09.12.2016 निरस्त हो चुका है तो उसकी पालना में दर्ज आदेश भी स्वतः ही निरस्त हो गये है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण दर्ज कर न्यायालय


के. 3.
 जिला कलेक्टर झुंझुनूं

AY

अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 09.12.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की है। नामान्तरकरण कार्यवाही है, जिससे हकूक तय नहीं होते हैं। प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4157 पर पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 में हमकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना अबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय के प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दरुतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जिला कलक्टर,
झुंझुनू
31/03/21

31